ललित कला अकादेमी में भ्रष्टाचार

*112. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ललित कला अकादेमी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने में अपनी बेबसी प्रकट की है;

(ख) यह अकादेमी किस संगठन के अधीन कार्य करती है और क्या यह अकादेमी मंत्रालय के प्रति जबावदेह है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री) (कुमारी शैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ललित कला अकादेमी सर्जनात्मक दृश्य कलाओं के क्षेत्र में कार्यकलाप को बढ़ावा देने एवं उनका समन्वय करने तथा इसके द्वारा देश की सांस्कृतिक एकता को प्रोन्नत करने वाला एक राष्ट्रीय संगठन है। अकादेमी भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। अकादेमी के कार्यकारी बोर्ड, सामान्य परिषद् और वित्त समिति में सरकार द्वारा नामजद व्यक्ति हैं। सभी स्वायत्त राष्ट्रीय संगठनों की तरह अकादेमी का अंतिम रूप से उत्तरदायित्व भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग के माध्यम से संसद के प्रति है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अकादेमी के लेखे की लेखा-परीक्षा करता है।

स्कूल न जाने वाले बच्चों के संबंध में प्रकाशित समाचार

*113. **श्रीमती सुषमा स्वराज:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 दिसम्बर, 1995 के "बिजनेस स्टैण्डर्ड" में "डोन्ट ब्लेम इट आन पावर्टी एलोन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बच्चों के स्कूल न जाने का प्रमुख कारण शिक्षा के स्तर का समय की आवश्यकताओं के अनुरूप न होना है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) कितने-कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते और कितने प्रतिशत बच्चे पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्व ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री) (डा० कृपासिन्धु भोई): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अध्ययनों से पता चला है कि प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के न जाने के दो मुख्य कारण हैं, सामाजिक आर्थिक विपन्नता तथा स्कूली वातावरण का अनुकूल न होना। जहां एक ओर राज्य सरकारें, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उचित कदम उठा रही हैं, वहीं दूसरी ओर केन्द्र सरकार आप्रेशन ब्लैकबोर्ड, शिक्षक शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षण के न्यूनतम स्तर, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम जैसे केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों की सहायता कर रही है।

(घ) इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 1994-95 में प्रकाशित चुन्निदा शैक्षिक आंकड़ों के अनुसार, पहली से पांचवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों का कुल नामांकन अनुपात 104% है। तथापि भिन्न-भिन्न राज्यों में इस अनुपात में अत्यधिक अन्तर है। एक अनुमान के अनुसार, प्राथमिक स्कूल में न जाने वाले बच्चों की प्रतिशतता 13% के लगभग है। वर्ष 1994-95 में पहली से पांचवीं कक्षाओं में पढ़ाई बीच में ही छोड़ जाने वाले बच्चों की दर 36% थी।

गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की दशा में सुधार करना

*114. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक तथा जीवनयापन की दशाओं में सुधार करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?